ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-12* January- 2018
Innovation The Research Concept

# अधोसंरचना विकास से ग्रामीण आर्थिक विकास की सम्भावनायें (2013–14)


**सारांश**

किसी भी अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं (infrastructure) की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं में परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन सुविधा के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएँ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है वे हैं, सिंचाई, विद्युत संचार ;बैंकिंग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि परिवहन प्रणाली तथा आर्थिक विकास के मध्य प्रत्यक्ष सह–संबंध पाया जाता है। आधारित संरचना से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उस पूँजी से होता है जो कि सड़क, रेल, विद्युत, शक्ति, संचार, पानी आधारभूत उद्योग आदि सार्वजनिक सेवाओं के रूप में विद्यमान होती है और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता आदि से संबंधित सामाजिक विशेषताएँ भी शामिल हो जाती हैं ।

**संगीता तिवारी**
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
श्री गुरूनानक महिला महाविद्यालय
जबलपुर, म0प्र0


**मुख्य शब्द :** अधोसंरचना विकास, ग्रामीण आर्थिक विकास

**प्रस्तावना**

अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की महत्वकांक्षा रखने वाले अल्पविकसित एवं अर्द्धविकसित देशों की प्रगति के लिए कुछ पूर्ण शर्तो की विवेचना की है।

प्रो. डब्ल्यू ए. लुइस के अनुसार आर्थिक विकास के लिए बचतों को प्रोत्साहन ज्ञान में वृद्धि को आवश्यक बताया है। विद्वानों इन्फ्रास्ट्रक्चर दो शब्दों से इन्फ्रा और स्ट्रक्चर से मिलकर बना है ''इन्फ्रा'' लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ढाँचा । इस प्रकार आधारभूत संरचना के अंतर्गत वह सभी कुछ आ जाता है जिससे अर्थव्यवस्था के ढॉचों को सम्बल तथा विकास को गति प्राप्त होती है। यदि वृहत रूप में आधारभूत संरचना की व्याख्या करें तो इसके अंतर्गत सीमेन्ट, लोहा, इस्पात, ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन संचार बैंकिंग स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा आदि सभी कुछ आ जाते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि आर्थिक विकास के सन्दर्भ में आधारभूत संरचना के अंतर्गत शक्ति, परिवहन व संचार का विशेष महत्व होता है।

अधोसंरचना से तात्पर्य मूलभूत ढॉचे से है जिसका मतलब नींव है इसको सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार कहा जा सकता है, चाहे वह कृषि से संबंधित हो या उद्योग से। कृषि उत्पादन के लिये संचालन शक्ति वित्त व परिवहन सुविधाओं आदि की आवश्यकता होती है। औद्योगिक उत्पादन के लिए केवल मशीनरी और संयंत्र ही नहीं चाहिए बल्कि कुशल जन शक्ति प्रबंध ऊर्जा, बैंकिंग व बीमा सुविधाओं की भी जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त विपणन, सुविधाओं, परिवहन सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। जिनमें रेलवे सड़के जहाजरानी, संचार सुविधाएँ आदि शामिल की जाती हैं । इन सभी सुविधाओं एवं सेवाओं को सामूहिक रूप से अधोसंरचना की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार बुनियादी संरचनाओं से अभिप्राय उन सुविधाओं क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन और विकास में सहायक होती हैं।

कुंजी शब्द– अधोसंरचना विकास, ग्रामीण आर्थिक विकास

**उद्देश्य**

1. अध्ययन क्षेत्र के महत्व एवं आवश्यकता की स्थिति का अध्ययन करना ।
2. ग्रामीण अधो–संरचना विकास के विभिन्न पहलुओं में अधो–संरचना की भूमि का अध्ययन करना ।
3. अधो–संरचना का विकास ग्रामीण क्षेत्र में अमूलचूल संरचनात्मक परिवर्तन लाता है।
4. ग्रामीणों की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना ।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार–''कृषि औद्योगिक विकास की आधार शिला है और कृषि उत्पादन औद्योगीकरण के लिए मूलभूत कार्यशील पूँजी है।''

कोल एवं हूबर ने कहा है कि– ''संम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि विकास पहले होना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र के अविकसित होने से दूसरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है तो वह अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा जो अन्य दोनों के विकास को बाधित करेगा।''

**व्याख्या**

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आधारित संरचना वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मात्र कुछ नये किस्म के आर्थिक विकास की स्थापना ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था में गति के द्वारा ऐसे आधारभूत परिवर्तन किये जाते हैं। जिसके द्वारा प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। कृषिजन्य एवं आधारिक संरचना के समुचित उपयोग एवं शक्ति के यांत्रिक साधनों के विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित संरचना का निर्माण करके तथा पूँजी के गहन विनियोग के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन संभव बनाना आधारिक संरचना का प्रमुख उद्देश्य है। ''राष्ट्र की उन्नति का सूचक कार्यरत आधारिक संरचना की कार्यत्मकता है । अतः अधोसरंचना की दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र ही आर्थिक रूप में सम्पन्न माना जाता है।

**कृषि विकास की संभावनाएं**

अतः किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अनुपात उसके अधोसंरचना विकास का महत्वपूर्ण बेरोमीटर माना जा सकता है। उद्योगों में उत्पत्ति ह्मास नियम लागू होता है जबकि कृषि के क्षेत्र में लम्बे समय के बाद होता है। अतः अधो–संरचना के माध्यम से कृषि से सम्बन्धित वस्तुए प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं और बाद में अन्य दोनों में ।

देखा जाय तो पूर्व उत्थानकाल में कृषि के विकास के साथ–साथ छोटे उद्योगों का विकास होना प्रारम्भ हो जाता है किन्तु स्वयं स्फूर्ति अवस्था में नये उद्योगों का शीघ्रता से विस्तार होता है। लाभ उत्पन्न होते हैं। जिनका बड़ा भाग कारखानों में पुनर्विनियोग कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था पूर्व अवशोषित प्राकृतिक साधनों तथा उत्पादन प्रणालियों का उपयोग करने लगती है जिससे उद्योग कृषि दोनों में ही नई तकनीकी का विस्तार होता है स्वयं स्फूर्ति अवस्था औद्योगीकरण और कृषि प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था तथा परिपक्वोन्मुखी अवस्था औद्योगीकरण और कृषि प्रक्रिया की उन्नत अवस्था का द्योतक है।

अधोसंरचना का एक प्रमुख लक्षण ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तन। अधो–संरचना का विकास एक ग्रामीण परम्परागत सामाज को जागरूक एवं विकसित ग्रामों में परिवर्तित करने का वास्तविक रास्ता है। इससे विश्व एक संगठित समाज जैसा दिखाई देने लगता है। स्वचलित वाहन हवाई जहाज, जल जहाज रेल सड़क परिवहन विद्युत शक्ति एवं अन्य अधोसंरचनात्मक तत्व सभी राष्ट्रों में समान दृष्टिगत होते हैं जिससे विश्व के सभी राष्ट्रों में एक समानता दिखाई देने लगती है। अधो–संरचना के अंतर्गत कृषि से उत्पादित वस्तु, पूँजी तकनीकी कुशल श्रम आदि का आयात–निर्यात से विश्व में आर्थिक मजबूती लाने में सहायक होते हैं।

किसी भी राष्ट्र में परिवहन व संचार की गतिशीलता वहाँ के अधो–संरचना के विकास की सूचक है। परिवहन व संचार की गतिशीलता तथा अधो–संरचना की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से उत्पादित वस्तुओं को शहर में उद्योगों की ओर प्रवाहित किया जाता है जिससे उद्योगों में उत्पादन कार्य के द्वारा कृषि से उत्पादित वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर इनकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है उत्पादकों की आय में वृद्धि होने लगती है। यह उत्पादन कार्य व परिवहन संचार की गतिशीलता अधो–संरचना के विशिष्टीकरण पर आधारित है, इसी प्रकार ग्रामीण आय परिवहन संचार की गतिशीलता एवं विशिष्टीकरण अधोसंरचना विकास का सूचक है।

अधो–संरचनात्मक प्रक्रिया से विकसित देशों से मशीन प्रोद्योगिकी, उर्वरक, तकनीशियनों एवं पूँजी आदि का हस्तांतरण प्रमुख है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत कम समय में हो जाता है। अधो–संरचनत्मक प्रक्रिया के द्वाा ग्रामीण विकास को अधिक गतिशील बनाने के लिये सरकारी हस्तक्षेप नीति अपनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था को विनिमय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना तथा अधो–संरचना का शीघ्र विकास करना है। सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सड़कों का विकास, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई आदि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की स्थापना करना, निजीक्षेत्र में अधो–संरचना के विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएँ, प्रदान करना तथा संतुलित विकास करना है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में निवेश का ढॉचा निर्धारित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि पूँजी–निर्माण की दर। परन्तु यह काम आसान नहीं है। अल्पविकसित देश को न केवल निवेश की दर बल्कि निवेश की संरचना भी निर्धारित करनी पड़ती है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि उस निवेश का वीणा उठाए, जो देश के लिए अधिकतम श्रेयस्कर हो।'' निवेश का इष्टतम ढॉचा अधिकतर निवेश के उपलब्ध मार्गो और विभिन्न प्रकार के निवेशों की सामाजिक सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर करता है। सामाजिक सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त विनियोजन की एक प्रमुख कसौटी है। यह सिद्धांत बताता है कि विनियोजन उस दिशा में किए जाएं जिनमें सामाजिक सीमान्त उत्पादकता अधिकतम हो।''

**निष्कर्ष**

निवेश अधिकतम उत्पादक दिशाओं में किया जाए ताकि निवेश से वर्तमान उत्पादन का अनुपात अधिकतम हो, अथवा विलोमतः पूँजी उत्पादन अनुपात न्यूनतम हो जाए। वे निवेश परियोजनाओं को अधिमान दिया जाए जो घरेलू कच्चे माल तथा अन्य क्रियाशील पूर्तियों का अधिकतम उपयोग करें। ऐसी निवेश परियोजनाएँ चुनी जाएं जो ग्रामीणों की वास्तविक आय में सुधार ला सके । अल्पविकसित देशों में यातायात एवं संचार के साधन अपर्याप्त होने के कारण इन देशों में साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता बाजार का आकार छोटा रहता है। व्यापार बड़े–बड़े शहरों में स्थित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित रहता है। इन साधनों के अपर्याप्त विकास के कारण उत्पादन लागतें ऊँची रहती

है। साथ–साथ देश में व्यापार का क्षेत्रीय असंतुलन बना रहता है। जबकि विकसित देशों में उन्नति का प्रमुख कारण अधो–संरचना के विकसित साधन हैं ।

**सुझाव**

1. ग्रामीण अधो–संरचना का विकास होना चाहिए ।
2. गग्रमीण क्षेत्रों के विकास से ही शहरी क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है।
3. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्रामीणों को होना चाहिये।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**


1. *अल्फ्रेड मार्शल ''इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड'' (1991)*
2. *रोस्टोव डब्ल्यू, डब्ल्यू ''स्टेजऑफ इकॉनामी ग्रोथ (कैम्ब्रिज 1960)*
3. *नरोत्तम शाह –इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दा इण्डियन इकॉनामी इकानॉमी बेदीलाल डाग्ली (स.) ''इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दा इण्डियन इकॉनामी (बाम्बे 1989)*
5. *ए.के.रे. ''इण्डियन इकानॉमी''(दिल्ली 1989) पृष्ठ 690*
6. *डॉ. पी. डी. माहेश्वरी भारतीय आर्थिक नीति पेज नं. 45–46*
7. *डॉ. शीलचन्द गुप्ता भारतीय अर्थव्यवस्था*
8. *वी.सी. सिन्हा भारतीय अर्थव्यवस्था पेज नं. 1*
9. *गुप्ता आर.सी. ''औद्योगिक अर्थशास्त्र'' आगरा बुक स्टोर आगरा (1982) पृ. 8*
10. *एम.एल. झिंगन विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन पेज नं. 20*
11. *शर्मा एवं सिंह आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं नियोजन के सिद्धान्त (1993) पृ.1*